Minister will come forward to this august House. . . .

MR. DEPUTY SPEAKER : He is also sitting there.

SHRI MALLIKARJUN : In the light of these, I request the hon Member to kindly withdraw his Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. George Joseph Mundackal, there is a request to withdraw the Bill.

SHRI GEORGE JOSEPH MUNDACKAL (Munattupuzha) : Some hon Members have said that have millions of people living below the poverty line. But they are always arguing for the increase of DA and all those things for the employees who are getting Rs. 2000 and 3000 rupees salary per month. I am not worried about it. About travelling, in my constituency there is not a single railway line. Do you want me to go by bullock cart ? Of course, I have got a railway pass in my pocket. . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you start in a bullock cart, when your term is over, you will reach your constituency. . . . (*Interruptions*)

SHRI GEORGE JOSEPH MUNDACKAL : I have requested only for minimum facilities to MPs for serving their constituency and for serving the people and I am pleading for all the MPs— so that they can honestly and effectively serve their constituencies. Anyway, as the Government is already seized of the matter, I am not pressing.

Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Membrs of Parliament Act, 1954.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act. 1954."

The motion was adopted.

SHRI GEORGE JOSEPH MUNDACKAL : I wtihdraw the Bill.

18.03 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

SUPPORT PRICE FOR WHEAT

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up the Half-an-hour discussion on support price of wheat.

Shri H. N. Bahuguna : I think the hon. Members will make it really an half-an-hour discussion.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज आधे घण्टे की बहस चल रही है। सच बात तो यह है कि पूरे दिन भर की या कम से कम दो दिन की बहस होनी चाहिए थी क्योंकि यह बहस एक मूल सवाल के साथ जुड़ी हुई है। एक प्रश्न इस सदन में हुआ था कि गेहूं का दाम कब अनाऊंस होगा ? उसी प्रश्न को लेकर आज यह चर्चा चल रही है। तब मंत्री जी ने कहा था कि जल्दी करेंगे और अब मंत्री जी ने इस सदन में गेहूं के दाम एलान किए हैं। इस संबंध में मुझे कुछ बातें कहनी हैं। समय बहुत कम है इसलिए मोटे-मोटे पाइन्ट ही बोल देता हूं।

पहली बात यह है कि जिस दल में माननीय मंत्री जी अब हैं उस दल का जो भूतपूर्व बुनियादी दल है जिसके आदि पुरुष प्रो० रंगा साहब यहां बैठे हुए हैं, इन सब ने भारत की जनता से वायदा किया था जिसमें थोड़ा बहुत मेरा भी हिस्सा रहा है कि सरकार खेत की पैदावार के दाम फसल बोने से पहले एलान करेगी। क्या यह सरकार किसी भी तारीख में उस वायदे को पूरा करेगी या नहीं करेगी, यह मैं जानना चाहता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस कुर्सी पर माननीय स्पीकर साहब की वजह से जब 204 नम्बर के सवाल पर

वहस चल रही थी तो स्पीकर साहब सरकार के खिलाफ फैसला कर चुके और उन्होंने कहा कि जल्दी कीजिए, दाम बताइए, गल्ला बाजार में आ रहा है। स्पीकर महोदय ने भी उस बात की ताईद की क्योंकि वे खुद काश्तकार हैं। काश्तकार तो राव वीरेन्द्र सिंह भी हैं, लेकिन इनकी काश्तकारी दूसरे लोग करते हैं, और इनका खेत की मेड़ से कोई रिश्ता नहीं है। इन्होंने अपने हाथ से न तो कभी गेहूं काटा है और न पता हो सकता है कि काटने वालों की क्या तक्लीफ है·····

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैंने इतना काटा है कि जितना आपने नहीं काटा होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह जाहिर है कि इनके मुकाबले में मैं तो इनके काश्तकार के काश्तकार का काश्तकार भी नहीं हूं। वह तो बहुत बड़े भूमिपति हैं। इसलिए जाहिर है उनके पास भूमि बहुत है। सीलिंग से कैसे बचाई होगी भगवान जाने।

राव वीरेन्द्र सिंह : बदली कर लो अपनी प्रोपर्टी से।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे मंजूर है, मेरी सारी सम्पत्ति और इनकी सम्पत्ति का बटवारा हो जाय और जो सम्पत्ति मुझे इनसे मिलेगी मैं उसको स्कूलों को दान कर दूंगा। पर यह अपने वचन पर दृढ़ रहें।

इनका वायदा आज साफ़ होना चाहिये कि दाम तय करायेंगे कि नहीं और बात तो गेहूं की है, अगले साल के गेहूं के दाम भी तय कर दीजिये। और अगर योजना चलानी है तो खरीफ के दाम भी तय कीजिये, और 5 साल के लिये कीजिये कि गेहूं का दाम, खाद का दाम, बिजली पानी का दाम यह होगा। इस का ऐलान कीजिये। रूस और चीन ने ऐसा किया है।

दूसरी बात यह है कि राव वीरेन्द्र सिंह ने गेहूं का दाम तय किया 151 रु०। सन् 1960 के मुकाबले में वित्त मंत्री कहते हैं कि रुपये की वैल्यू घट कर 20 पैसे रह गई है। तो कृषि मंत्री जी का दाम गेहूं को 1960 के मुकाबले में हो गया एक बटे पांच, यानी 30 रु०। अब क्या किया? ए०पी०सी० ने 150 रु० कहा था तो 1 रु० राव साहब की सरकार ने दक्षिणा और दे दी कि 151 रु०। अब यह किस हिसाब से दिया?

आप देखें कि आज बाजार भाव क्या है। मेरे पास 8 अप्रैल का "इकोनामिक टाइम्स" अखबार है जिसमें गेहूं का बाजार भाव निकला है : हापुड़ ऐवरेज 200 से 210 रु०, हापुड़ फार्म 220 से 230 रु०, जयपुर 175 से 240 रु०, कानपुर 180 से 230 रु०, करनाल जो राव वीरेन्द्र सिंह की रियासत का जिला है वहां आर्डिनरी गेहूं का भाव है 183 से 186 रु०, करनाल सुपीरियर फ़ार्म 192 से 198 रु०, करनाल शरबती 188 से 193 रु०, करनाल मैक्सिकन 180 से 182 रु०, मुरादाबाद दड़ा 200 से 260 रु०, मेरठ फ़ार्म सुपीरियर 250 से 275 रु०, मेरठ दड़ा 200 से 215 रु०, मोगा फ़ार्म 170 से 175 रु०, मोगा दड़ा 158 से 162 रु०, मोगा मैक्सिकन 158 से 164 रु०, मोगा पलवन 167 से 173 रु०, रोहतक दड़ा 170 से 200 रु०, रोहतक फ़ार्म 210 से 230 रु०, रोहतक सुपीरियर 235 से 250 रु०, सोनीपत फ़ार्म 200 से 225 रु०। यह तो आपके हरियाणा के भाव हैं, और राव वीरेन्द्रसिंह ने देश के संसद में भाव कर दिया 151 रु०। बाजार में काश्तकार को ऊंचा भाव मिल रहा है और सरकार कह रही है 151 रु० काफी है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का बाजार भाव क्यों लूटा जा रहा है इस सदन के द्वारा ? क्या वजह है सरकार ने कम भाव रखा ? तीसरा सवाल यह करना चाहता हूं सरकार कहती है हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ी हाई ईल्डिंग वैराइटीज़ में पैदावार की। इस सरकार का हाल क्या है वह बता दूं। इस सरकार ने कहा गल्ले में हमने आत्म निर्भरता पैदा की। पिछले 30 साल में हम 60 मिलियन टन से 130 मिलियन टन पर जरूर आ गये। लेकिन पैदा कितने में हुआ ? 130 मिलियन हैक्टर में। राव बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने 1 हैक्टर में 1 टन गल्ला पैदा किया। पड़ोसी चीन में क्या है ? 100 मिलियन हैक्टर में 300 मिलियन टन गल्ला। यानी एक हैक्टर में 3 टन। और हमारे मंत्री जी हेक्टर पीछे 1 टन में ही प्रसन्न हैं, मग्न हैं, खुश हैं। अच्छा खुश रहिये, परन्तु इससे देश का तो काम बनता नहीं।

तीसरी बात सुनिये, कितना बुरा हाल है ये फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा रहे हैं। अगर आप 200 रुपये टन फर्टिलाइजर पर सबसीडी दे देते तो कुल सबसीडी 140 करोड़ रुपये पड़ती। अगर इतनी सबसीडी दे दोगे तो अन्न का इम्पोर्ट बिल कम होगा 280 करोड़ रुपये के बराबर।

इस सरकार को समझाने के लिए एक स्कूल खोलने की आवश्यकता है जहां कि इसको समझाया जाये। एग्रीकल्चर कमीशन की किताब देखने की इनको फुरसत नहीं है। इनके यहां झगड़े बहुत हैं। कौन मंत्री रहे और कौन जाये। कौन मुख्यमंत्री रहें और कौन जाये ? किसको खिसकाओ ? राव साहब की चिन्ता थोड़े दिन के लिये दूर हो गई है क्योंकि श्री भजन लाल जी अमेरिका चले गये हैं, लेकिन खिसकाओ, बैठाओ, खिसकाओ। मेरा कहना है कि गल्ला खिसकाओ आगे, नहीं सारा देश मर जायेगा। गरीबी दूर होने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

मैं सब काम छोड़कर तैयार हूं।

श्री हरीश रावत : इधर आ जाइये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इधर-उधर क्या ? मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैंने इन्हें बचपन से देखा है, अब इनको क्या कहूं ? जैसे किसी बड़े को अपने छोटे बच्चों को ऊपर आते हुए देखकर खुशी होती है, इनको यहां देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। जब में मुख्य मन्त्री था तो यह मेरे दल में थे ब्लाक प्रमुख थे। लेकिन इनका दल बाद में इंदिरा दल हो गया और मैं अलग हो गया।

पंजाब स्टेट प्लानिंग बोर्ड कह रहा है, पंजाब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बोल रहा है कि पंजाब का जो रोटेशन था पहले क्राप का, वह भूमि के लिये लाभप्रद था। मन्त्री जी ने बड़ी तारीफ की है कि पंजाब में धान बहुत पैदा होना है। एक दिन राव साहब ने बोला कि दक्षिण भारत वालो क्या बोल रहे हो, धान तुम्हीं पैदा नहीं करते हो, धान तो हम पैदा कर रहे हैं पंजाब में। लेकिन हालत क्या है, लुधियाना यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन से बात कोटेड है पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर प्लानिंग बोर्ड ने बोला है कि व्हीट-मेज रोटेशन जब तक रहा तब तक जो पैदावार थी, उसमें कम खाद डालकर ज्यादा गल्ला पैदा होता था। जब से व्हीट राइस रोटेशन हुआ है, तब से मामला गड़बड़ हो गया। खाद ज्यादा लग रही है पैदावार निस्बतन कम मिल रही है।

मुख्य बात यह है कि क्रापिंग पैटर्न पर ध्यान देंगे या नहीं, धरती को बचाने के लिए ?

सही दाम तो क्या दोगे ? पर इतना ही बताइये कि माटी का परीक्षण कराया है कि कितनी खाद पड़ेगी किस गांव के खेत में। किस गांव में माटी कैसी है ? राव साहब को पता ही नहीं होगा कि माटी का परीक्षण हो रहा है या नहीं। हां खाद पड़ रहा है।

मैं आपको बता दूं कि क्या फर्क पड़ा है। पंजाब में जब से यह धान पैदा करने लगे हैं, तब से यह गड़बड़ हुई है। यह एक ग्रेट ग्रीन रेवोल्यूशन है भारत डोगरा का जिसमें उन्होंने स्टेट प्लानिंग बोर्ड को कोट किया है।

यह अंग्रेजी में है। उन्होंने लिखा है कि जब गेहूं के बाद धान पैदा होता है तो साढ़े 13 के०जी० गेहूं पैदा होने के लिये 1 के०जी० फर्टीलाइजर लगता है पर जब व्हीट और मेज की साइकिल चलती है तो उस वक्त 20 के०जी० व्हीट होता है एक के०जी० नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पर। एक नाईट्रोजन यूनिट साढ़े 13 में ये प्रसन्न हैं और इनको पता नहीं है कि धरती नष्ट हो रही है और नाइट्रोजन ज्यादा लग रहा है, किसान के पैदावार दाम ज्यादा लग रहे हैं।

हमें यह बता दें कि फ़ार्मर तक टेक्नालाजी पहुंचाने का इनका क्या तरीका है ? दाम जो यह बढ़ा रहे हैं, उससे प्रोडक्टिविटि का किसान को क्या फ़र्क पड़ा है ?

इनकी किताब आर्थिक समीक्षा है। इसमें पृष्ठ 81 में लिखा है कि गेहूं कैसा हो रहा है। 1955-56 में गेहूं कितना था और आज कितना है। 1978-79 में गेहूं 35.5 मिलियन टन था और 1981-82 में राव साहब ने कहा कि 37.83 मिलियन टन। देखिये तो सही, क्या तेज चल रहे हैं ?

राव साहब से पूछा जाये कि करनाल बंट ने क्या हाल कर दिया। मैं इन्हीं की किताब से पढ़कर सुना दूंगा। यह किताब है टाटा कंसल्टैंसी की। इनकी बहुत दोस्ती है टाटा कंसल्टैंसी से। इनसे मतलब राव साहब से नहीं, बल्कि इनकी सरकार से है। यह सरकार बिरला और टाटा की सरकार है। उसका कहना है कि 1968-69 में फ़र्टीलाइजर का इम्पोर्ट बिल 133 करोड़ रुपए का था और गल्ले का 337 करोड़ रुपए था। टोटल इम्पोर्ट हो गया 470 करोड़ रुपए। और पार साल राव साहब ने 1,000 करोड़ रुपए का फ़र्टीलाइजर मंगाया। अब यह सरकार सैल्फ़-सफ़िशेंसी की तरफ काम नहीं कर रही है। सारी कठिनाई यह है कि किसान के ढंब के सम्बन्ध में कोई बुनियादी नीति नहीं है। उसको दाम भी नहीं मिल रहा है और उसे सही रास्ता भी नहीं बताया जा रहा है।

नहरों के किनारे के सारे खेत डूब रहे हैं। मेरे साथी श्री रामलाल राही, को अभी सीतापुर में अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए पानी में बैठना पड़ा-72 घंटे एक बार और 23 घंटे एक बार। तब सरकार की समझ में आया। क्या सीपेज का कोई इलाज नहीं है।

इस, हाउस में एक क्वेस्चन के जवाब में में राव साहब ने कहा कि ए० पी० सी० में एक एक्सपर्ट है। इस मामले में रंगा साहब मेरी गीता हैं ? मैं उन्हीं को कोट करता हूं—आज से नहीं, जब में स्वयंसेवक था और अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपने महान नेताओं की चप्पल उठाता था, तब से किसानों के बारे में उनके भाषण मैं सुन रहा हूं। रंगा साहब ने कहा कि किसानों के नुमायंदे और रखो। राव साहब ने कहा कि एक तो है, और कितने रखूं फिर भी रंगा साहब ने कहा कि यह ऐसा जरूर करेंगे। फिर कोई मेम्बर

बोला, तो कहा कि उन्होंने वचन दिया है, यह करेंगे। भगवान जाने, ए० पी० सी० कैसा बनेगा। कौन देखने वाला है।

नई वैरायटीज़ कितनी पैदा हुई हैं? हर साल कहा जाता है कि इतनी नई वैरायटीज़ निकली हैं। मन्त्री महोदय बतायें कि गेहूं की कोई ऐसी वैरायटी है, जिसको कीड़ा न लगे। हरियाणा और पंजाब में करनाल बंट ने क्या गज़ब किया है! अगर मैं पढ़ कर सुना दूं, तो सदन को पता चलेगा कि इस देश की हालत कितनी खराब है। करनाल बंट एक फंगस डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में बहुत नुक्सान हुआ है। 1980-81 में इसका इतना फैलाव हो गया कि यह राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तराई रिजन और बिहार में भी फैल गया। इकोनोमिक टाइम्ज ने 31 जून, 1981 को लिखा :—

> "Karnal Bunt has spread over eight districts of Punjab where disease has been detected according to an official survey to the extent of 13% to 43% in samples collected from these areas,"

लेकिन करनाल बंट का कोई इलाज उनके पास नहीं है। अगर एग्रीकल्चरल प्रास-पेरिटी लानी है, किसान का भला करना है, तो साइंटिस्ट्स को कोई डिजीज़-फ्री सीड तैयार करने के लिए कहना चाहिए। मगर बेचारे साइंटिस्ट तो आत्म-हत्या करने पर मजबूर हैं। आज व्यवस्था ऐसी है कि उसको काम नहीं करने दिया जाता, सारा ब्यूरो-क्रेटिक मामला चल रहा है।

किसान को पैसा देने में तो राव साहब की सरकार को बहुत तकलीफ है। एफ़० सी० आई० की जो सबसिडी दी जाती है, उसमें से रोडेंट-चूहे-कितना खाते हैं और ट्रांसिट में कितना लास होता है? खाने वाले को जो सबसिडी दी जा रही है, वह कितनी है और एफ़० सी० आई० के मिसमैनेजमेंट, टोटली ग़लत मैनेजमेंट के कारण में कितनी है? मैं उनमें से रहा हूं, जो कहते हैं कि यह काम पब्लिक सैक्टर से लेना चाहिए। लेकिन आज पब्लिक सैक्टर की स्थिति यह है कि एफ० सी० आई० का चेयरमैन कौन बनेगा, उसमें कौन रहेगा? जिसको सरकार चाहे। हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है : जिसको पिया चाहे, वही सुहागिन। यह नहीं देखा जाता है कि आदमी लायक है या नालायक है।

मैं तो कहता हूं कि प्राईवेट फूड ट्रेड के सब से योग्य आदमी को उसका चेयरमैन बनाओं और उसे कहो कि अगर वह उसी परसेंटेज पर इस कार्पोरेशन को नहीं चलाएगा, जिसपर वह अपना काम चलाता था, तो हम उसको सज़ा देंगे। आज यह सरकार फूड कार्पो-रेशन के मिसमैनेजमेंट को सबसिडी दे रही है और किसान के दाम काट रही है। वह कहती है कि 151 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। यू० पी० सरकार इनकी सरकार है, मेरी सरकार नहीं है। उसकी रीकमेंडेशन है कि 200 रुपए देने चाहिए। मन्त्री महोदय बताएं कि इस बारे में उसका क्या कहना है। या तो वह सरकार* है या समझने वालों की समझ गायब हो गई है। दो सौ रुपया उस सरकार ने क्यों बतलाया और 151 इन्होंने क्यों कहा?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : आपका असर पड़ गया होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उत्तर प्रदेश के तीन चौथाई मंत्री जो अब तक हुए हैं और भारत के प्रधान मंत्री तक बड़े लम्बे अर्से तक मेरे असर में रहे हैं और उस असर के बड़े-बड़े फल निकले हैं। आपको भी असर लेना हो तो मुझे गाली देना शुरू कीजिए, आपको अच्छा पोर्टफोलिया मिल जाथेगा और आप मुझ को

* Expunged as ordered by the chair.

रोज दावत पर बुलाना शुरू कर दीजिए तो आप का डिस्मसल हो जायेगा ।

मेरा चार्ज है कि यह सरकार लूट करती है । सरकार मुनाफाखोरी कैसे करती है वह बताना चाहता हूं । राव साहब के प्रान्त हरियाणा का ही उदाहरण देना चाहूंगा । पारसाल इन्होंने गेहूं का दाम तय किया 142 रुपया क्वींटल । पंजाब वालों ने 138 और 142 के बीच में गेहूं खरीदा । आपने फेयर एवरेज व्हीट का दाम 151 रुपया बोला है । उसका मतलब यह है कि उस एवरेज से नीचे वाले गेहूं का दाम कम होगा । तो पिछले साल पंजाब ने 138 और 142 के बीच में गेहूं खरीदकर 180 और 188 रुपये में खुले बाजार के लिये ट्रेडर्स को बेचा । उन्होंने क्या भाव बेचा, उससे इस सरकार का क्या मतलब । इसी तरह से हरियाणा में गेहूं 140-142 के बीच में खरीदा गया और 175-180रुपये में डीलर्स को खुले बाजार में ले जाने के लिए बेचा गया । हरियाणा की एक खासियत और भी है । कुरुक्षेत्र में पाण्डवों की जीत कभी-कभी ही होती है, वहां का कौरव दल बड़ा शक्तिशाली है । मेरा चाज है कि हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीदा उसमें से 25 हजार टन बंगाल के रोलर फ्लावर मिल्स को बेच दिया । किस भाव पर ? 165 रुपए क्वींटल के भाव पर । खरीदा 140-142 में और बेचा 165 में । मैं स्पेसिफिक चार्ज लगा रहा हूं** आप समझ लीजिए कितने करोड़ की बात होगी ? सवाल यह है कि जो गल्ला सरकार लेती है उसमें मुनाफाखोरी क्यों करती है ? दूसरी तरफ पहाड़ों पर गल्ला गायब है । मैंने प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखा । उन्होंने कहा कि लिख आप ठीक रहे हैं ! हमारे यहां गांवों में गल्ला नहीं पहुंच रहा है ।

एक बात और है । सरकार कहां है, इसकी कोई पहचान प्रधान मंत्री ने नहीं छोड़ी है । अगर होम मिनिस्टर यहां हैं । तो इन्टेलिजेंस वहां है । एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां हैं सिविल सप्लाई वाले गायब हैं । गेहूं इनके पास तो गन्ना उनके पास । इनको पकड़ो तो वह उधर और उनको पकड़ो तो ये इधर । सारी अव्यवस्था है। प्रधान मंत्री का अधिकार तो है मंत्रिमंडल को बनाना लेकिन यह अधिकार नहीं है कि डिपार्टमेन्ट्स को नष्ट कर दें, अर्थ-व्यवस्था को चौपट ना कर दें । आज पहाड़ पर गल्ला नहीं पहुंच रहा है । मेरे दोस्त अभी वहां से घूम कर आए हैं, इनकी बात मैं मान लूंगा, ये कह दें कि सभी जगह गल्ला पहुंच रहा है । पांच रुपए किलो से कम पर आटा पहाड़ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है । इतना बुरा हाल है । आपने रोलर फ्लोर मिल का दाम 205 रुपए क्वींटल बताया है, यह किससे मत्थे जायेगा : कह रहे हैं पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ाते थे, इस बार ज्यादा बढ़ा दिया है । इन्होंने 151 रुपया तय करके किसानों को लूटा है । बाजार भाव जो मिल रहा है, वह मैंने अभी आपको बताया है । खाने वाले को राव साहब आपने क्या दिया है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : आप ही बता दीजिए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप ही बता दीजिए मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ।

राव वीरेन्द्र सिंह : 172 रु०

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इसके मायने यह हुए कि एक क्विंटल 172 रु० में मिलेगा । फेयर प्राइस शौप पर मान लीजिए मेरा कार्ड दो किलों का है, तो मुझे देना पड़ेगा 3 रु० 44 पै०- तो इस प्रकार एक पैसा कहां से आएगा । खैरीज बाजार नहीं है । देश में दो लाख से ज्यादा फेयर प्राइस शाप्स हैं । इस सरकार ने दुकानें बढ़ाई हैं और उनके द्वारा बिकने वाला गल्ला घटाया है । वह एक पैसा

* Not Recorded.

आप दुकानदार को दिलाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि 172 में मिलेगा, लेकिन मिलेगा 173-174 में। किसी भी हिसाब से आप लगा लीजिए, खाने वालों को ज्यादा देना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप चलकर किसी भी सामान को खरीदिए, यदि एक या दो पैसे वापिस लेने हैं, तो वे नहीं मिलेंगे। फेयर प्राइस शाप पर गल्ला दे रहे हैं, लेकिन मेरे नौकर को तीन घण्टे वहां बैठना पड़ता है, कार्ड पर गल्ला लेने के लिए। कार्ड में मेरे नौकर का नाम जोड़ना था, तो पता नहीं कितने दिनों से पालियामेंट हाउस में कार्ड पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होता है। सवाल यह है जैसा कि प्राण चोपड़ा साहब ने कहा है कि फेयर प्राइस शाप्स पर जितना रुपया लगाना पड़ता है, उसे देखा जाए और जो जाप्ते का मुनाफा है उसे समझा जाए तो उसमें उनको तीन सौ रुपए माह से ज्यादा नहीं बचते हैं। मगर ईमानदारी से काम न करे तो कोई फेयर प्राइस शाप्स 6 हज़ार रुपए से कम नहीं कमा रही है। किसान लुट रहा है खेत में, खाने वाला लुट रहा है बाज़ार में-ऐसे हैं हमारे कृषि मंत्री राव साहब और ऐसी है हमारी आज की सरकार की व्यवस्था। मेरी मांग है, किसानों को मत लूटो, खाने वाले को मत लूटो। मेरी प्रार्थना है कि स्वराज के वायदे को मत तोड़ो, किसान के दम को मत तोड़ो। हर एक चीज़ का दाम एक फसल पहले एलान कर दो, अगर आप सचमुच देशभक्त हैं, अगर आप सचमुच किसान भक्त हैं। मैं मानता हूं कि आप देश भक्त तो हैं, पर उससे भी ज्यादा टाटा भला है। क्यों कि सरकार से इनको देश टाटा और बिरला में ही दिखाई देता है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि किसान को मत लूटो। यदि उसके पास पैसा होगा तो वह साईकिल खरीदेगा, रेडियो खरीदेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेगा, लेकिन किसान लुट जाएगा तो कुछ नही होगा।

दूरदराज के पहाड़ी इलाके की लाहल-स्पीति की बात भी कर रहा हूं, केदार-बद्री की बात भी कह रहा हूं, पिथौरागढ़, उत्तर-काशी, चमौली और अल्मोड़ा की बात भी कह रहा हूं—गल्ला सारे इलाकों में नहीं है। चाहे मिनिस्टर आपके दूसरे हो गए हों, उनको कह दो मेहरवानी करके, लोगों को जिन्दा रहने दें, किसान लुट गया तो उसको बचाइए, खाने वाले मर गए तो उनको बचाने की कोशिश कीजिए।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस आधे घण्टे की बहस का यह फैसला निकलेगा कि खरीफ का फौरन दाम एलान हो जाएगा। रबी का दाम अगले सीजन के पहले, सितम्बर से पहले-पहले, एलान हो जाएगा। मैं और फसलों की क्या कहूं आप कह देंगे कि यह गेहूं की बात पर बहस है। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि आधे से ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश और बिहार में जल जाएगा। इस सदन में मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कृपा करके आप उसका इन्तजाम कीजिए, वरना इस देश की अर्थ व्यवस्था के ऊपर जो कड़वा बोझ आ रहा है और टूट आ रही है, उसके लिए यह सरकार इतिहास और इस देश के भविष्य की नज़र में दोषी रहेगी।

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Bahuguna, when you spoke, you said something about some amount being shared.

SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour) : I have put my objection to that.

MR. DEPUTY SPEAKER : I see that. Therefore, I will go through the records.

SHRI AMAL DATTA : It is not correct.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Datta, I have already told you.

SHRI H. N. BAHUGUNA : I am merely saying two things. I have made two submissions : that the Haryana Government purchased wheat in the market from peasantry at between Rs. 140/- and Rs. 142/- last year. Then they sold out to open dealers, not to fair price shops, at Rs. 175/- and Rs. 180/- respectively. Third, they sold wheat and I stand by what I am saying ; they sold wheat —to Roller Flour Mills of Bengal to the tune of 25,000 tonnes, at a rate of Rs. 165/-.

Now, who has sold it? Haryana Government. And if the Haryana Government has sold it, who else is responsible ? I would like to know why Rs. 165/- to Roller Flour Mill and why higher money for the consumer ? Therefore, the suspicion is that there has been some fishy deal.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is an allegation. There, fore I will go through the record.

SHRI H. N. BAHUGUNA : You can see it.

MR. DEPUTY SPEAKER : I will go through the record.

Now the Minister.

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि श्री बहुगुणा जी ने किसान के हक में आवाज़ उठाई है। लेकिन जो बातें इन्होंने कही हैं, वे बार-बार हाउस में, इस से पहले कितनी ही बार डिस्कस हो चुकी हैं। करीब-करीब हर चीज़ का जवाब हम दे चुके हैं। इस बार इन का एक ही ऐतराज़ था कि गेहूं की कीमत कम मुकर्रिर की गई है और वक्त से पहले मुकर्रिर नहीं हुई...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बोने से पहले।

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, बोने से पहले। कीमत मुकर्रिर करने में हम जल्दी करते हैं, लेकिन खास तौर से बोने से पहले कीमत मुकर्रिर करना हमेशा किसान के लिये लाभदायक चीज़ नहीं हो सकती है। यह कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत मर्तबा ऐसा होता है—अगर 6 महीने पहले हम कीमत मुकर्रिर कर दे, गेहूं बोई जाती है। नवम्बर में—हार्वेस्टिंग होता है मार्च के आखिर में और अप्रैल में, इस बीच में कहीं डीज़ल की कीमत बढ़ सकती है, कहीं बिजली की कीमत बढ़ सकती है ऐसी सूरत में भाव को बार-बार रिवाइज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, जिन के लिये किसान को खर्च करना पड़ता है, उन का भी अन्दाज़ा करना पड़ता है।

हम ने अपने टर्म्ज़ आफ रेफ्रेन्स 1980 में रिवाइज़ किये थे। जो चीज किसान अपने इस्तेमाल के लिये खरीदता है और किसान की पैदावार जिस कीमत पर बिकती है—उन में कुछ पैरिटी होनी चाहिये, इस का ध्यान एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन रखेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोशिश हम यह करते हैं, ज्यों ही ठीक मौका हो, उस में अन्दाज़ा लगा कर कैबिनेट में कीमत तय कर दें। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद हमारी काफ़ी लम्बी विल है। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की रिपोर्ट पर ही स्टेट गवर्नमेंट्स से कमेंट्स लेते हैं। आम तौर पर सब स्टेट्स से जवाब आने में देर लग जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब स्टेट गवर्नमेंटस से जवाब आ जाते हैं तो हम दूसरी मिनिस्ट्रीज़ से कमेंट्स लेते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फूड और सिविल सप्लाईज़ से। उनके नज़रिये को सामने रखना पड़ता है। उसके बाद

फिर जो हमारा ख्याल बनता है कि कितनी कीमत होनी चाहिए, उस पर सरकार तय करती है कि क्या कीमत हालात को देखते हुए, उस वक्त जब कि फसल आने वाली हो, तब का जाय। इस बार कुछ दिनों की देरी ज़रूर हुई है, मैं मानता हूं। क्योंकि बावजूद इसके कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश में अभी फसल मंडियों में नहीं आई है अप्रैल में कटाई शुरू होती है, इस लिए अप्रैल में फसल आनी शुरू होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो सूखे इलाके हैं फसल कुछ वक्त से पहले पहुंच जाती है। लेकिन इसके लिए ज्यादा परेशानी बहुगुणा जी को यों नहीं होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जिस किस्म का गेहूं आता है, उसकी कीमत तो किसान को पहले हा अच्छी मिलती है। प्रोक्योरेमेंट प्राइस, जो सरकार तय करती है, वह एक किस्म की यह गारण्टी है कि उससे नीचे दाम किसानों को मंडियों में नहीं मिलेंगे और अगर ऐसा होगा तो जो कुछ भी किसान मंडी में लायेगा उसको सरकार खरीद लेगी। इस लिए जो दाम मुकर्रिर होता है, उससे ऊपर किसान का बिकता है जिसकी वजह से उसको नुकसान नहीं होता है। यह एक खुली चीज़ है—अगर हमारे भाव से नीचे किसान को दाम मिलता है, तो हमारे भाव पर वह हमको बेच दे, इसमें कोई रुकावट नहीं है। इस लिए, डिप्टी स्पीकर साहब जी बात बहुगुणा जी ने कही है उसमें कोई वजन मुझे नज़र नहीं आता है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि 151 रुपये कीमत कम मुकर्रिर हुई है। मुझे माफ़ करें, मैं बहुगुणा जी का ध्यान तीन साल पहले जो हालात थे उन की तरफ़ दिला दूं। प्राइसिज भी इनके सामने हैं। जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसमें बहुगुणा जी भी एक बहुत बड़े सदस्य थे, उस समय आपने गेहूं का भाव 110 रुपये तय किया था। इसके बाद दुबारा 112 रुपये 50 पैसे कर दिया था। फिर उसके बाद आपने किसान को फायदा पहुंचाने के लिए जो कि बहुत कोशिश की थी वह यह की थी कि वह 112 रुपये 50 पैसे का भाव 115 रुपये कर दिया था। यह आपकी जनता गवर्नमेंट ने किया जिसमें आप बहुगुणा जी शामिल थे, वजीर थे। अब आप देख लीजिए कि जब से आपने गवर्नमेंट छोड़ी, उसके बाद से हम इन तीन वर्षों में इन भावों को कहां ले गये हैं। गेहूं के दाम को 115 रुपये से बढ़ा कर 151 रुपये कर दिये हैं।

(व्यवधान)

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Other prices have also risen.

SHRI H. N. BAHUGUNA : I would like him to reply to Prof. Ranga's point.

राव वीरेन्द्र सिंह : हमने इस साल 142 रुपये से 151 रुपये दाम किये हैं। पिछले साल हमने 130 रुपये से 142 रुपये किये थे। यानी 12 रुपये की वृद्धि की थी। उस से पहले 117 रुपये से बढ़ा कर हमने 130 रुपये किये थे।

एक माननीय सदस्य : रुपये की कीमत भी तो कम हो रही है।

राव वीरेन्द्र सिंह : रुपये की पहले भी कीमत हमेशा गिरती आयी है और कीमतें बढ़ती रही हैं। हर चीज का उससे मुकाबला न करें। आप यह देखें कि सरकार ने इन तीन सालों में किसान को अच्छी कीमतें देने के लिये कितना कुछ किया है। उन तीन वर्षों में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बहुगुणा जी

आपने कर के दिखाया था ? गन्ने की मिसाल ले लीजिए। आपने 38 लाख टन शूगर की पैदावार को छोड़ा था, 79-80 में। हमने पिछले साल तक 38 लाख टन से बढ़ा बढ़ा कर शूगर की पैदावार को तीन साल में 84 लाख टन पर पहूंचा दिया है। अब हिन्दुस्तान सारी दुनिया में सब से बड़ा चीनी पैदा करने वाला देश बन गया है। (व्यवधान) आप भूल गये उन दिनों को जब जनता राज में बताशे ढूंढ़ते फिरते थे। आज शायद आप मिठी लस्सी पीकर आये हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस साल जितना गन्ना जलेगा, उतना पहले कभी नहीं जला था।

राव वीरेन्द्र सिंह : बहुगुणा जी कहें कि गेहूं के लिए कुछ नहीं हुआ, अगर वे ध्यान दें तो मैं उनको बताता हूं कि गेहूं के लिए क्या कुछ नहीं हुआ है। (व्यवधान) आप मुझे तरीका बता दीजिए कि कैसे हम गेंहू की पैदावार बढ़ा सकते हैं। हम उस पर अमल करेंगे।

हमारे यहां 1974-75 में पर हेक्टेअर ईल्ड 1358 के० जी० नेशनल एवरेज था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप एक हेक्टअर में कितना पैदा करते हैं, चीन कितना पैदा करता है ? आप चीन में जा कर देखिये, अब तो वहां के दरवाजे खुले हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : सन् 1974 के मुकाबले में आज हम 1696 के० जी० पर हेक्टेअर ईल्ड कर रहे हैं। इसमें हमारे साइंटिस्टों का भी योगदान है। उन्होंने बीज भी अच्छा पैदा किया है, डिजीज रजिसटेंट भी है, बीमारी भी कम लगती है। नयी नयी वैराइटीज के बीज पैदा किये गये हैं। इसमें एग्रीकल्चरल रिसर्व इन्स्टीच्युट और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का भी योगदान है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : फांसी पर जो लटक रहे हैं, में उनकी बात कर रहा हूं।

इस तरीके से गेहूं की पैदावार बढ़ती रही है। सन 1977-78 का तो बहुगुणा जी ने बताया कि 31 मिलीयन टन से कुछ ऊपर था। फिर 1978-79 में बेशक फसल बहुत अच्छी हुई। वह भगवान की मेहरबानी थी, मौसम बहुत अच्छा था। उससे ज्यादा उससे पहले कभी नहीं हुई थी, 35.5 मिलीयन टन पैदा हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि 1979-80 में आपकी दया से सूखा पड़ा।.....(व्यवधान) किसके ऊपर नज़ला था ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Rao Birendra Singh Ji, he can also take the credit. For a longer time he has been in Congress Party.

SHRI H. N. BAHUGUNA : Much longer than him.

राव वीरेन्द्र सिंह : उस समय 31.81 मिलियन टन की पैदावार हुई। लेकिन एक हीं साल में इस सरकार के बनते ही 31.83 मिलियन टन से बढ़कर 36.3 मिलियन टन पर पहुंच गई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या किया ?

राव वीरेन्द्र सिंह : किसानों को हमारे ऊपर एतबार हुआ। किसानों को समय पर अच्छे बीज पहुंचाए गए। आई० आर० डी० का प्रोग्राम हमने सारे मुल्क में लागू किया

और 5011 ब्लाक्स को इसमें शामिल किया। एन० आर० इ० पी० का प्रोग्राम भी अच्छा चला और इरीगेशन को इस तरह से बढ़ावा दिया गया जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। तीन मिलियन ज़मीन को इरीगेशन करना कोई मामूली बात नहीं है। जो कुछ हुआ उसको आप भूल जाते हैं। पिछले साल भी मौसम इतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी हमने जिस तरीके से अच्छे बीज पहुंचाए, जिस तरीके से प्लानिंग की, जिस तरीके से हाई-इल्डिंग वैरायटीज को बढ़ाने की बात की, नयी टैक्नोलौजी एक्स-टेशन के ज़रिए से पहुंचायी, डिमान्सट्रेशन दिया, मिनी किट्स तकसीम किए, वह सब फ़ारमर्स को पता है। जहां पर गेहूं की इल्ड बहुत कम है, वहां हमने पर यूनिट इल्ड बढ़ाने की कोशिश की है। पंजाब, हरियाणा, और वैस्टर्न यू० पी० में फसल अच्छी है। दो मिलियन टन से ज्यादा गेहूं की फसल बरबाद हो गई लेकिन फिर भी 37.8 मिलियन टन गेहूं पिछले साल पैदा हुआ। यह एक आल टाईम रिकार्ड था। हालाँकि, सब जानते हैं कि देश में अब भी सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन किस-किस तरीके से क्या-क्या उपाय किये गये और क्या-क्या सुविधायें किसानों को दी गई, वह हम जानते हैं। हर स्टेट में जाकर हमारे आफिसर्स कहते हैं कि किसानों को पानी बिजली, बीज और खाद समय पर दो। अच्छे बीज पहुंचाये भी गए हैं।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि 40 मिलियन टन की हमने पैदावार की और इस साल भी उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी पैदावार होगी। आप अन्दाज़ नहीं कर सकते थे कि किस तरीके से पैदावार बढ़ रही है? किस तरीके से किसानों को अच्छा भाव मिला। गेहूं का एरिया बढ़ा है घटा नहीं है। नहीं तो किसान पैदा करना छोड़ देता जैसे आपके समय में खेतों में आग लगा दी थी और गन्ना बोना छोड़ दिया था। इस तरीके से हमने कोशिश की है कि किसानों को पूरा भाव मिले। सरकार इस बात को महसूस करती है कि यदि किसानों को खेती की पैदावार के लिए कोई इन्सेन्टीव देना है तो उन्हें पूरा भाव मिलना चाहिए। बहुगुणा जी के और हमारे विचार यहां मिलते हैं, लेकिन मुश्किल यह हैं कि जो हम कर रहे हैं उसकी तारीफ उसके मुंह से नहीं निकलती। क्योंकि उन्होंने कसम खा ही रखी है कि सरकार को क्रिटीसाइज करने की बात करो।

श्री सत्यनारायण जटिया : सारी बुराइयां हमारी तरफ भेज दीजिए।

राव वीरेन्द्र सिंह : गेहूं की कीमत मुकर्रर करने के बाद मन्डियों में तुरन्त इन्तजाम करने की कोशिश की जाती है और उसी की वजह से किसानों को पूरा लाभ पहुंचता है। अब कहीं कहीं अगर कोई इरिगुलैरिटी होती है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स खुद मुख्तार हैं, ऐग्रीकल्चर स्टेट का सबजेक्ट है, हम तो स्टेट्स को उत्साह दिलाते हैं, इमदाद करते हैं, जब कभी सूखा या फ़लड आता है तो असिस्टेंस भी देते हैं, किसानों को जो नुकसान होता है सूखे या फ़लड से यह किसी कुदरती हादसे से तो अच्छी फसल पैदा करने के लिये दिल खोल कर भारत सरकार ने इमदाद दी है। अब तक 407 करोड़ रु० की रैडीशनल असिस्टेंस दी है स्टेट्स को। कुछ स्टेट्स के मैमोरेन्डा आ रहे हैं। यह सारी किसानों की इमदाद है।

आपने कहा एफ० सी० आई० को जो सबसिडी दी जा रही है उसका लाभ किसानों को नहीं पहुंचता। जो एफ० सी० आई० को

नुक्सान उठाना पड़ता है डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेक अप मैं कई बार दे चुका हूं, चाहेंगे तो बाहर फिर दे दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कृपा कर के भिजवा देना।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं भिजवा दूंगा। ज्यादा खर्चा उस पर मंडियों के टैक्सेज और ट्रांसपोर्ट चार्जेज हैं, साथ ही कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वह भी हैं, गोदाम के चार्जेज हैं और लौसेज़ भी हैं चाहे वह कीड़ों से हो, चूहों से होकर आदमी भी खा जाते हैं। तो यह डिस्ट्रिब्यूशन पर खर्चा है। एक पौलिसी देश ने अपनायी है कि बफर स्टाक रखना है। देश में 12 से 18 मिलियन टन तक होना चाहिए और कौशिश करते हैं कि 20 मिलियन टन का बफ़र स्टाक हो। अगर इतना भारी बफ़र स्टाक नहीं होता तो 1979-80 में जिस तरीके से सूखे का मुकाबला किया और बाहर से एक दाना अन्न नहीं मंगाना पड़ा, यह बफ़र स्टाक की वजह से ही हुआ। इसकी आपको तारीफ करनी चाहिये। एक आदमी भूखा नहीं मरने पाया उस सूखे में भी।

माननीय बहुगुणा जी को एक छोटी सी बात और समझानी है। यह कहते हैं कि 172 रु० जो भाव मुकर्रर किया उसके हिसाब से 1 रु० 72 पैसे प्रति किलो अनाज लोगों को मिलेगा और खरीज़ की शोर्टेज होने से व्यापारी उपभोक्ताओं को लूटेंगे। बहुगुणा जी बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं वह यह समझ लें कि 172 रु० एफ़०सी० आई० की इशू प्राइस है, रिटेल प्राइस नहीं। इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा रेड करेगी। एफ०सी०आई० से जो मिलेगा स्टेट को वह 172 रु० पर मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि रिटेल में 1 रु० 72 पैसे कंज्यूमर को मिलेगा। तो वहां यह बराबर हो जाएगा, आप चिन्ता न करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : समझ में आ गया। और लूटो।

राव वीरेन्द्र सिंह : गेहू का प्रोक्योरमेंट जितना होता है सैन्ट्रल स्टाक के लिये उसका 96 परसेंट पंजाब, हरियाणा और यू० पी० से होता है, और इसके अलावा चावल भी 76 फीसदी इन तीन राज्यों से ही इकट्ठा होता है। तो अगर यह दोनों फसलें, गेहूं और चावल की, इन इलाकों में न ली जायें तो देश में बहुत भारी कमी होगी। आप चीन से जब मुकाबला करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिये कि पंजाब चीन से कम पैदा नहीं करता है क्योंकि वहां एक ही खेत से गेहूं और चावल की दो फसलें ली जाती हैं।

रही बात सीपेज, वाटर लागिंग और मैलिनिटी की तो उसका हम इलाज करते हैं। खाद का किस तरह से सही इस्तेमाल हो वह भी सिखाने की कोशिश की जा रही हैं। इतनी चिन्ता की बात नहीं। क्योंकि हिन्दुस्तान में फर्टिलाइजर की कंजम्पशन अभी बहुत कम है। नैशनल एवरेज हमारी 30,32 के० जी० पर हैक्टर है जब कि दूसरे देशों में 400,500 के० जी० तक है। सिर्फ पंजाब, हरियाणा में 100 के० जी० पर हैक्टर से ऊपर है, बाकि स्टेट ऐसी हैं जहां 10,12 के० जी० पर हैक्टर भी नहीं बनती।

MR. DEPUTY-SPEAKER : In China, not only wheat but all foodgrains are taken together. There everything is taken together. That is the maximum. It is not only wheat, but all grains.

RAO BIRENDRA SINGH : Sir, he has objected to. . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : We exclude all other grains, but say this.

SHRI H. N. BAHUGUNA : This is very bad.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What I say is, in China they include all grains, but here we take only wheat. We should not compare with China in respect of wheat only, but all other foodgrains.

SHRI H. N. BAHUGUNA : With due respect to you, Sir, what I read out was total production of foodgrains in India compared to China. 130 million hectares produced, I told him, 135 million tonnes. In China, 100 million hectares produced 300 million tonnes of foodgrains.

RAO BIRENDRA SINGH : So they include all the other crops also. They include in food production food crops like potato also.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes.

(*Interruptions*).

RAO BIRENDRA SINGH : You are asking about wheat. If you talk about potatoes, we will tell you how we increased production in respect of potatoes also.

(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Bahuguna, you must know our country is a democratic country.

(*Interruptions*)

SHRI H.N. BAHUGUNA : Sir, he is talking about Punjab. In Gujarat it is not even 11 compared to 50 pr 60 of Punjab. What are you talking ? It is different all over the country. Don't talk about Punjab only.

(*Interruptions*)

RAO BIRENDRA SINGH : The States which have a very low yield per unit have to increase their yield. That is our strategy and unless that is done, the food production all over the country cannot reach the levels that we are trying to achieve.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अपने बाद की पीढ़ी का भी ध्यान रखो ।

राव वीरेन्द्र सिंह : इन्होंने करनाल बंट की बात कही, डिजीज फ्री पैदा करने की बात कही । हमारे रिसर्च इन्स्टीट्यूट ज्यादातर काम ही करनाल बंट पर कर रहे हैं । करनाल बंट फैल गया है, इसमें शक नहीं । लेकिन इसकी वजह से ईल्ड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा । बहुत कम असर पड़ा है, व्हीट प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है । मेरी निगाह में इसकी वजह से 1, डेढ़ परसेंट से ज्यादा कम नहीं होता है जहां करनाल बंट लग भी जाये ।

श्री हेमवती बगुहुणा : मैंने फिगर्स पढ़े हैं आपके ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मुझे पता है कि आप जानते हैं थोड़ा बहुत । कोशिश यह होती है कि हाई इल्ड वैराइटी बढ़े । बाजरे, मकई व्हीट व राइस की पैदावार बढ़ी है, आप जानते हैं कि किस तरह से ईल्ड बढ़ी है । कहां से कहां हिन्दुस्तान पहुंचा है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Include sugar also. Sugarcane and everything you must include. Mr. Rao Birendra Singh, you must include sugarcane and eyerything. Then only we will be No. 1 in the world.

RAO BIRENDRA SINGH : Yes.

मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें श्री बहुगुणा जी ने उठाई थीं, उनका जवाब उनको मिल गया है ।

कोशिश हम यह करेंगे आइन्दा तजुर्बे के तौर पर जो बहुगुणा जी ने कहा है, मुझे इससे इन्कार नहीं, कि इस बार खरीफ की फसल आ रही है, हम बोने से पहले ही उसकी कीमतें मुकर्रर करेंगे और आप हम तजुर्बा करेंगे कि उसका किसानों पर क्या असर होता है । उसका नतीजा सामने आ जायेगा । अगर उससे किसान को लाभ पहुंचता है तो हम

रबी के लिये भी ऐसा करेंगे, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बगुहुणा : लेकिन बीच में खाद, बिजली और पानी के दाम मत बढ़ा देना।

राव बीरेन्द्र सिंह : सब कुछ कह लिया बहुगुणा जी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Mr. Amal Dutta. I would request each one of you, Mr. Amal Dutta, Mr. Harish Rawat, Mr. Rajesh Kumar Singh and Mr. Satyanarayan Jatiya, to put one question each, no speech. All of you may put one question each. Already half-an-hour has gone to one hour. He took half-an-hour to put questions and the Minister took half-an-hour to reply.

(*Interruptions*).

SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour) : Considering the total production of foodgrains in India, the amount procured by the Government and distributed though the public distribution system is only about 9 to 10%. Is it not possible for the Government to give the producer of wheat who has shown a great increase in production by adopting new technologies, a remmunerative price ? Will the Government not consider declaring a price which will be remunerative to the farmer considering the increase in price of inputs, considering the increase in price of other commodities which the farmers have to buy, and particularly having regard to the fact that the procurement price is relevant only to farmers who have no power to hold back the stocks and have to sell more or less immediataly after harvest ? Therefore, will the Government not consider Increasing this to Rs. 165/- having regard to the suggestions given by the Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh Governments respectively of Rs. 170/-, Rs. 175/-, Rs. 180/- and Rs. 200/- per quintal, which would give some relevance to the Government's policy of not straightway accepting the Agricultural Price Commission's suggestions but also consultation with the State Governments ?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमने किसानों के हिमायतियों की बात सुनी। एक तो माननीय सदस्य, गढ़वाल, जिन्होंने अभी हल नहीं चलाया।

MR. DEPUTY SPEAKER : You put a question, sharp question. Do not make a reference to any other thing. If you make references, then everybody will take a long time. Plea se put your question straightway. Minister will reply to every point.

श्री हरीश रावत : पहले यह प्रैक्टिस रही है कि इस बारे में चीफ़ मिनिस्टर्ज के व्यूज लिए जाते थे और उसके बाद प्रोक्युरमेंट प्राइस घोषित की जाती थी। इस बार कुछ चीफ मिनिस्टर्ज ने अपने मेंट्स भेजे और कुछ वहां पेज पाए और उनको प्रापर टाइम नहीं दिया गया। इस मामले में यह ढीलें क्यों हुई ? जिन स्टेट्स ने अपने कमेंट्स भेजे, उन्होंने क्या प्रोक्यूरमेंट प्राइस फ़िक्स करने की सिफारिश की थी ?

श्री बहुगुणा ने एक बहुत सुन्दर प्रश्न उठाया है कि इस तरह सबसिडी पर पैसा खर्च करने के बजाए मन्त्री महोदय क्यों नहीं फिनांस मिनिस्ट्री से सिफारिश करते कि फ़र्टिलाइजर पर से एक्साइज ड्यूटी या तो पूर्णतः समाप्त कर दी जाए या कम कर दी जाए, ताकि किसान को सस्ते दाम पर फ़र्टिलाइज़र मिल सकें और वह अपने उत्पादन को और अधिक बढ़ा सके और लोगों को गेहूं और पैडी की प्राइस बार-बार बढ़ाने की वकालत न करनी पड़े।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या पार्टी में रहने का इरादा नहीं है ?

श्री हरीश रावत : पिछली बार पैडी के मामले में दिक्कत आई है। सरकार ने कहा कि हम फूड के मामले में सारे कंट्री को एक

जौन मान कर चलेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने रेगुलेशन के नाम पर या अपने टैक्सिज़ की उगाही करने के नाम पर इन्टर-स्टेट या इन्टर-डिस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन्ज़ इम्पोज़ कीं। इस तरह सारे कन्ट्री को एक ज़ोन बनाने की बात लागू नहीं हो पायी है। विशेषकर आंध्र प्रदेश और यू० पी० ने, और कुछ हद तक मध्य प्रदेश ने भी, ऐसी रेस्ट्रिक्शन्ज़ लगाई, जिसकी वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हुई है विशेषकर उन एरियाज़ में जो डेफ़िसिट हैं। इस को एन्फोर्स करने के लिये आप क्या करना चाहते हैं ?

19.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only questions should be asked. You should frame it in such a way as Mr. Harish Rawat and Mr. Amal Datta did.

SHRI RAJESH KUMAR SINGH (Firozabad) : Sir. the Minister has said in his reply;

> "The terms of reference of the Agricultural Prices Commission were amended and now the A. P. C. is required to keep in view the terms of trade between the agricultural and non-agricultural commodities-the consumer goods."

दोनों की तुलना करने के बाद एक जगह पर वे फिर कहते हैं ;

> "···· it has not been possible to achieve a better parity between the index prices of agricultural produce and the non-agricultural produce."

पिछले साल इन्होंने 135 रुपये से 142 रुपए तय करके 12 रुपए क्वींटल की वृद्धि की थी। इस साल इन्होंने 9 रुपए क्वींटल की वृद्धि की है। यह सरकार विदेशों से 40 लाख टन गेहूं मंगवा सकती है जिस पर विदेशी मुद्रा में 50 रुपए क्वींटल अधिक दाम, यहां की तुलना में, दे सकती है—यह सरकार का कौन सा फार्मूला और नीति है ?

आपने अपनी तकरीर में यह भी कहा है कि जनता सरकार के मुकाबले में तुलनात्मक दृष्टि से आपने कीमतें ज्यादा बढ़ाई हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जनता सरकार के समय में डीज़ल की कीमत क्या थी ? एक रुपए 47 पैसे लीटर का भाव था जो कि अब साढ़े तीन रुपए से भी ऊपर है। इसी तरह से फर्टिलाइजर की एक बोरी 54 रुपए में आती थी जो कि अब 130 रुपए की है। इसी तरह से आपने बिजली का रेट पांच बार बढ़ाया है। ट्रैक्टर की कीमत उस समय क्या थी और आज क्या है ? इसके अलावा आपने बैंक से ऋण लेने की सुविधा और फर्टिलाइजर पर जो सहायता दी जा रही थी उसको भी समाप्त कर दिया है। गर्ज कि किसान के काम में आने वाली जो भी चीजें हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।

इसके अलावा किसी साल अगर आलू ज्यादा पैदा हो गया तो सड़ जायेगा और गन्ना ज्यादा पैदा हो गया तो जला दिया जायेगा। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आप क्राप पालिसी, कृषि नीति कब निर्धारित करने जा रहे हैं। आपने क्राप इन्श्योरेंस की स्कीम बनाई है लेकिन सही मायने में अभी वह लागू नहीं है तो उसको आप कब लागू करेंगे ? सरकार को चाहिए कि क्राप पालिसी निर्धारित करे जिससे कि किसानों की सुरक्षा हो सके।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहस काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न करने के लिए भी कुछ न कुछ आधार चाहिए। इस देश की बहुसंख्य जनता खेती पर निर्भर करती है और उसकी जो औसत आमदनी है वह गरीबी की रेखा से भी

नीचे है जिसका अर्थ यह है कि किसानों की आय बहुत ही कम है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसी भी उद्योग के अन्दर जो कुछ लागत लगती है, उस लागत के आधार पर ही उसके भाव निर्धारित होते हैं । इसलिए मैं साफ-साफ पूछना चाहता हूं कि क्या खेती में जो लागत लगती है, उस लागत के आधार पर ही किसान को कृषि उत्पादन का मूल्य मिलेगा या नहीं ? इस पर मैं सरकार की राय जानना चाहता हूं । दूसरे यह देखने में आया है कि फर्टिलाइजर की कंजम्पशन कम होती जा रही है । इसका मूल भूत कारण यह है कि सिंचाई की क्षमता उपलब्ध नहीं है, इसलिए खाद की खपत कम होगी ।

MR. DEPUTY SPEAKER : No body speaks about consumers like us.

श्री सत्य नारायण जटिया: इसलिए मेरा कहना यह है कि सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने पर विचार कर रही है ? प्राय: गावों में सब जगह तालाब उपलब्ध नहीं हैं, उसके कारण फलो-इरिगेशन नहीं मिलता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कुवें से सिंचाई करनी है तो डीजल, और बिजली के दाम बढ़े हुए हैं । कुंवा बनाना है तो सीमेंट के दाम बढ़े हुए हैं । जब इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में, चाहे रेल के किराए की बात या मोटर के किराए की बात हो, किसानों के उत्पादन के दाम भी बढ़ने चाहिएं । किसान को सारी सुविधा मिल नहीं पाती है । जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और रुपए की कीमत घट रही है, उसी अनुपात में आप किसान को क्या देने वाले हैं ?

RAO BIRENDRA SINGH : Sir, some more points have been raised by the hon. Members and I will reply to them briefly.

The remunerative price is always intended to be paid by the Government. But we have to keep a balance as you rightly observed, between the price that is paid to the farmer and also the price which consumers have to pay. We have to look after the consumers also. The farmers also are consumers in a big way. The people who grow foodgrains, do not grow sufficiently for themselves even. They have also to purchase foodgrains and other agricultural produce from time to time. Therefore, it is not a question of farmers only being at the receiving end of the price for their produce. They also have to pay. Mostly, throughout the year, the farmers are out of stock and and they have also to go to the market. It is not only the other consumers but farmers have also to be included in the category of consumers.

SHRI AMAL DATTA : When the farmer goes to the market, does he get the foodgrains from the public distribution system ?

RAO BIRENDRA SINGH : Why not ? There is no bar to farmers also getting foodgrains from the fair price shops wherever these are opened by the Government.

SHRI H. N. BAHUGUNA : You purchase only 10 per cent. 90 per cent is in the open market. All of us know that urban areas along are covered by rationing. Only cities like Calcutta are under statutory rationing. Otherwise, even in these towns many people are without the facility of fair price shops.

MR. DEPUTY SPEAKER : Even when the price is fixed at Rs. 1.51, the open market price is Rs. 1.70 or Rs. 1.80. Supposing the price is fixed at Rs. 1.80, immediately the open market price will go beyond that.

PROF. N. G. RANGA : What about the cost of production ?

MR. DEPUTY SPEAKER : What I am saying is, will not open market prices go up ? Then everybody would find it difficult.

RAO BIRENDRA SINGH : All prices will go up. Food is a basic necessity. The prices are bound to react, if food prices spurt.

Ours is a free economy. We have to maximise procurement, if distribution has to be run and, therefore, although the country to one food zone—it has been kept as one food zone—with a view to enable people to get these food supplies from other States also. Otherwise, if we confine the to State only, procurement will be increased, but then other deficit States might suffer. Therefore, even though some States may be imposing certain restrictions to maximise procurement, our policy is, the Hon. Member himself has admitted, that procurement is only about 10% of the production, 90% of the production finds free market and that should be sufficient for the farmers who can hold their stocks to sell wherever they like.

SHRI H. N. BAHUGUNA : That is the big farmer. The small one is selling under distress to you.

RAO BIRENDRA SINGH : Procurement prices are meant only to help primarily the small farmers who cannot retain their stock.

PROF. N. G. RANGA : That is why it should be there early enough.

RAO BIRENDRA SINGH : We have agreed to that.

If the Government does not move into the market, if there is no intervention with support price, you know what will happen, how the market will be exploited by traders. It always happens at harvest time, if the Government does not purchase in the market, the prices fall.

The States' recommendations were received. Shri Harish Rawat wanted to know. We wrote to the Chief Ministers on 8th November, after receipt of the recommendations of the APC, as early as on 8th of November and then we kept on reminding them also. But the replies from the States were received from Haryana on 19-1-83, from U. P. on 25-1-83 and from Punjab on 10th February and various other replies were received, before 10th February, 83. That way, we had to wait.

PROF. N. G. RANGA : There has been delay.

RAO BIRENDRA SINGH : Shri Harish Rawat wanted to know about the prices recommended. The prices recommended by the Chief Ministers range between Rs. 150 and Rs. 200/- It is not correct that UP recommended Rs. 200/-. UP's recommendation was Rs. 186, not Rs. 200/- as Mr. Bahuguna said.

SHRI SATYANARAYAN JATIYA : What about Madhya Pradesh ?

RAO BIRENDRA SINGH : It was probably Rs. 200/- That was the only State.

SHRI H. N. BAHUGUNA : You choose the lowest.

RAO BIRENDRA SINGH : Not that. As I said if the prices recommended by the States are not realistic, the Central Government connot accept the prices recommended by the Chief Ministers. We have to think in terms of the whole country and the consumers also along with the farmer. It is true that fertiliser prices had gone up but ferti liser prices have not been raised since March last year. What Shri Rajesh Kumar Singh said namely prices of induts should not go up at all is accepted, then this would also mean that the cost of production, also will remain the same and then there would have been no need to fix the price at Rs. 151 when the previous price also might have continued. Therefore, Hon. Members know that, as has been explained several times in this House, all inputs which go into cost of production are taken into consideration by the APC while recommending the prices and the rise in input price is also fully accounted for.

Mr. Jatiya wanted to know what was being done whether there was a crop policy, whether irrigation was being looked after. I have said earlier that three million hectares of land are to be brought under irrigation annually. That is our Plan target for this year and the next year . . .

श्री सत्यनारायण जटिया : 1978-79 की तुलना में आपके सिंचाई के रकबे में वृद्धि हुई है तो फिर आपका प्रोडक्शन कैसे कम हो गया ? This is my simple question-

RAO BIRENDRA SINGH : Production has not increased to the extent that we wanted or we would have wished because most of the land in India is still under dryland farming. Even after we have fully utilised our irrigation potenriue a larger portion of land in India will still remain unirrigated and will have to depend on the monsoon. But we are looking after dryland farming. It is only through new technologies, conservation of moisture and soil, and water, harvesting methods adopted by farmers and various other hings that go into better production in dryland areas, it is only through new technologies, that we can bring up the total production in the country and we are paying attention towards that. Even in the Budget speech the Finance Minister announced that Rs. 125 crores would be the Central allocation for looking after small and marginal farmers and particularly in dryland areas because small and marginal farmers had been left out of the benefits after the IRD programme was revised and modified. But now they will be receiving greater attention and dryland farming is one of the important points now stressed by the Prime Minister under her now 20-Point Programme.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned to reassemble at 11.00 a.m. on Monday, April 11, 1983.

19.18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 11, 1983/Chaitra 21 1905 (Saka).